कृपया प्रकाशनार्थ **14 सितंबर 2011**

कुष्ठपीडितों ने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली,सितंबर 14: कुष्ठपीडित कलंकरहित, सम्माननीय व उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके तथा देश से कुष्ठरोग का निर्मूलन हो इसलिए कार्य करने का अभिवचन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे कुष्ठपीडींतों के प्रतिनिधियों को आज दिया. पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक के नेतृत्व में कुष्ठपीडितों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति महोदया को मिला. इस प्रतिनिधि मंडल में नॅशनल फोरम ऑफ लेप्रसी अफेक्टेड पर्सन्स के अध्यक्ष डा. पी.के. गोपाल, इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियन के अध्यक्ष डा. शरद्चंद्र गोखले, हिंद कुष्ठ निवारण संघ के श्री. उदय ठकार, महाराष्ट्र कुष्ठपीडित संगठन के अध्यक्ष श्री. बळीराम तांबडे, संजय नगर रहिवासी संघ, मुंबई के अध्यक्ष श्री. भीमराव मधाले तथा दिल्ली के कार्यकर्ता श्री. एस. के. दत्ता शामिल थे.

इस विषय की पृष्ठभूमि बताते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''कुष्ठपीडितों के लिए काम करनेवाले कुछ प्रमुख कर्मठ समाजसेवक तथा कुष्ठपीडितों की कुछ बस्तीओं के प्रतिनिधिओं के साथ मैंने कुष्ठपीडितों की समस्याएं तथा उनके सबलीकरण के संदर्भ में एक याचिका राज्यसभा को 5 दिसंबर 2007 को प्रस्तुत की थी. समिति के तत्कालिन अध्यक्ष श्री. वेंकैया नायडू के नेतृत्व में याचिका समिति ने कई राज्यों का तथा कुष्ठपीडितों की अलग-अलग बस्तीयों का दौरा किया. अध्ययन तथा विचार विमर्श के बाद इस समिति ने 24 अक्टूबर 2008 को राज्यसभा में अपनी रपट पेश की. अलग-अलग मंत्रालयों से प्राप्त जवाब, उनसे हुए विचार विमर्श के बाद याचिका समिति ने 22 नवंबर 2010 को सभागृह में की गयी कारवाई के संदर्भ में रपट (ए.टी.आर) प्रस्तुत किया. आरंभिक रपट तथा 22 नवंबर के रपट में कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए कई सुझाव दिए गए जिनसे हमें काफी संतोष प्राप्त हुआ था.''

''चूँकि समिति के सुझाव अलग-अलग मंत्रालयों से संबंधित थे, हमने उनपर शीघ्र कार्यान्वयन हो इसलिए प्रधानमंत्री से मिलना उचित समझा. इसलिए हमने 1 जनवरी 2011 को पत्र लिख कर उनसे समय की प्रार्थना की. 20 जनवरी तथा

..2..

10 फरवरी को फिर से पत्र लिख कर उन्हें स्मरण दिलाया. मगर कुछ भी जबाब न मिलने से हमने आखिर 9 मार्च 2011 को उन्हें 'संकट संदेश' (SOS) पत्र भेजा. उसे भी कोई जबाब नहीं मिला. प्रधानमंत्री का संवेदनाहीन रवैये से हम काफी दुःखी हुए. इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासंघ की आमसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया. 25 मार्च 2011 के प्रस्ताव क्र. 65/215 में महासंघ द्वारा कुष्ठपीडित तथा उनके परिवारजनों के प्रति भेदभाव का निर्मूलन तथा इसके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए. इस घटना के बाद हमने देश के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात् राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया. तद्नुसार आज हमने अपने सुझाव व माँगे महामहीम राष्ट्रपति जी के सामने रखी'', ऐसी जानकारी श्री. राम नाईक ने दी.

प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को निम्न माँगों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध कियाः 1) कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन नीति का निर्माण, 2) याचिका के में निर्दिष्ट 16 कानुनों में सुधार, 3) कुष्ठपीडितों के भरण-पोषण के भत्ते में प्रति माह रु. 2,000/- तक बढोत्तरी तथा सभी राज्यों में समान भत्ता, 4) गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों को तथा अपाहीजों को मिलने वाले सभी सामाजिक तथा वित्तिय लाभ कुष्ठपीडितों को भी प्रदान करना, 5) कुष्ठपीडितों की बस्तीओं को नागरी सुविधाएं प्रदान करना, 6) कुष्ठपीडितों के बच्चों को उच्चशिक्षा के साधन तथा छायावृत्ति, 7) कुष्ठपीडितोंद्वारा निर्मित वस्तुओं पर वैट न लगाना, 8) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य उपक्रम की राज्य तथा जिलास्तरीय समितिओं तथा कुष्ठपीडितों के केंद्रिय पुनर्वसन मंडल पर कुष्ठपीडितों का नामांकन, 9) कुष्ठ रोग में कितनी बढोतरी हुई / निर्मूलन हुआ यह देखने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण व 10) कुष्ठरोग से संबंधित सेवाओं में कुष्ठपीडितों की सहभागिता बढ़े इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मार्गदर्शक सुझावों का कार्यान्वयन.

''महामहीम राष्ट्रपति के साथ हुअी चर्चा तथा उनके आश्वासन से हमें काफी संतोष है. आश्वासनों के कार्यान्वयन का हम बेसबरी से इंतजार करेंगे'', ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अंत में कहा.

(कार्यालय सचिव)